

एनएसजी कमांडो से हेलीपैड और सेफ हाउस तक, जी-20 समिट के वीवीआईपी की सुरक्षा को ये खास इंतजाम

नई दिल्ली। जी-20 समिट के दौरान आईटीपीओ में होने वाले सम्मेलन के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए विशेष तौर पर हॉल संख्या 4 के पास हेलीपैड तैयार किया गया है। जरूरत पड़ने पर एनएसजी के विशेष कमांडो हेलीकॉप्टर की मदद से यहां ऑपरेशन चलाएंगे और वीवीआईपी को इसी हेलीकॉप्टर से सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए एनएसजी के कमांडो बीते दो माह से लगातार अभ्यास कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर वीवीआईपी की गाड़ी को भी हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियां किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहती हैं। कुछ समय पहले गृह सचिव अजय भल्ला ने आईटीपीओ का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने पुलिस को सलाह दी थी कि इमरजेंसी के लिए हेलीपैड बनाने की संभावना देखी जाए। उनके निर्देश के बाद एनएसजी के साथ हुई बैठक में भी यह मुद्दा उठया गया था। एनएसजी की तरफ से साफ किया गया था कि आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर से ही उन्हें ऑपरेशन चलाना होगा। इसलिए प्रगति मैदान में हेलीपैड बनाया जाए। सूत्रों ने बताया कि हॉल संख्या 4 के समीप हेलीपैड तैयार कर लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि आपातकालीन हालात से निपटने के लिए आईटीपीओ से लेकर होटलों, एयरपोर्ट और राजघाट के पास सुरक्षित जगह (सेफ हाउस) बनाए गए हैं, ताकि तत्काल वीवीआईपी को वहां शिफ्ट किया जा सके। आतंकी हमले से निपटने के लिए एनएसजी के 200 कमांडो दिल्ली में तैनात रहेंगे। हाल ही में उन्होंने अक्षधाम में भी हेलीकॉप्टर से बचाव ऑपरेशन के लिए अभ्यास किया गया है। ड्रोन हमले से भी निपटने के लिए एनएसजी की विशेष टीम यहां तैनात रहेगी।

एनडीआरएफ की टीम भी मुस्तैद रहेगी-
सूत्रों ने बताया कि बेहद महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम होने के चलते आतंकी हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सुरक्षा को हर तरह से मजबूत किया जा रहा है।

ममता और नीतीश को जल्दी चुनाव का क्यों सता रहा है डर, मुंबई की मीटिंग में करेंगे चर्चा

ऐसी आशंका सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही जून में दोहराई थी और कहा था कि यह जरूरी नहीं है कि लोकसभा के चुनाव अगले साल ही हों। ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें पहले ही करा लिया जाए और इस साल भी ये हो सकते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए ममता बनर्जी ने पिछले दिनों कहा था कि सरकार पहले ही चुनाव करा सकती है क्योंकि वह तीन राज्यों में हर के बाद लोकसभा चुनाव में नहीं उतरना चाहती। उनकी इस आशंका के बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कहा कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार चाहते हैं कि विपक्ष की मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को

होने वाली मीटिंग में भी जल्दी चुनाव की संभावना पर चर्चा की जाए। इस बार की बैठक में INDIA गठबंधन के दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर भी बात हो सकती है, जो एकता की सबसे अहम कड़ी होगा। यही वजह है कि नीतीश और ममता जल्दी चुनाव पर चर्चा चाहते हैं ताकि आगे सीटों के बंटवारे पर बात हो सके और चुनाव की तैयारियों में भी सारे दल जुट सकें।

इस मीटिंग में INDIA गठबंधन का लोगो, मुख्यालय और संयोजक फाइनेल हो सकते हैं। कयास है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को ही संयोजक बनाया जा सकता है, जबकि 11 अन्य दलों से सह-संयोजक हो सकते हैं। हालांकि पंच सीटों पर ही फंसेगा क्योंकि बिहार, बंगाल, यूपी जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दल खासे मजबूत हैं और कांग्रेस भी आसानी



से त्याग नहीं करना चाहेगी। पिछले दिनों अखिलेश को देखे थे कि कांग्रेस को ऐसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों को यादव और ममता बनर्जी तो इस बात पर सहमत भी हो सपोर्ट करना चाहिए, जहां वह कमजोर है।

भाजपा और मोदी सरकार के इन कदमों से भी बढ़ी आशंका
जल्दी चुनाव होने का डर नीतीश और ममता बनर्जी जैसे नेताओं को इसलिए भी सता रहा है क्योंकि भाजपा की तैयारी भी तेज है। चर्चा है कि वह जल्दी ही लोकसभा उम्मीदवार भी तय करना शुरू कर देगी। यही नहीं जिस तरह एलपीजी गैस के दामों में 200 रुपये की कटौती की गई है और तमाम योजनाओं का खुद पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं, उससे भी ऐसे कयास लग रहे हैं। भाजपा संसदीय दल की बैठकों में भी पीएम नरेंद्र मोदी सांसदों को लगातार संदेश देते रहे हैं कि वह जनता के बीच जाएं और सरकार की योजनाओं का प्रचार करें। साफ है कि भाजपा महीनों पहले से ही चुनावी मोड में है और इसी से विपक्ष की आशंकाओं को बल मिल रहा है।

बिहार में भीषण हदसा, हड़दवे पर कंटेनर में घुसी स्कॉर्पियो

सात लोगों की मौत

सासाराम। बिहार के सासाराम में भीषण सड़क हदसे में सात लोगों की मौत हो गई और चार लोग गंभीर घायल हैं। हदसा रोहतास जिले के शिवसागर थाना इलाके में नेशनल हाइवे नंबर 2 पर बुधवार अलसुबह करीब 3 बजे हुआ। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार हड़दवे पर कंटेनर में घुस गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग फंस गए। बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें निकालकर अस्पताल ले जाया गया। मरने वालों में तीन बच्चे एवं दो महिलाएं शामिल हैं। सभी मृतक कैमूर जिले के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सुदेश्वर शर्मा अपने परिवार के साथ बोधगया से अपने गांव कैमूर जिला के सबार थाना क्षेत्र के कुराड़ी वापस लौट रहे थे। तभी



अहले सुबह स्कॉर्पियो चालक को झपकी आ गई, और उनकी गाड़ी आगे जा रही एक कंटेनर में पीछे से जा भिड़ी। घटना में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। टोल प्लाजा के हाईड्रॉ गाड़ी से स्कॉर्पियो को कंटेनर से बाहर खींच कर निकाला गया। हदसे में छह की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। जबकि एक की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। चार लोग बुरी तरह से

जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य बना दिया जाएगा, 31 अगस्त को विस्तृत बयान देगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की किस समय सीमा के बारे में सोचता है, इसके बारे में उसे आधिकारिक तौर पर अवगत कराये। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सुर्य कांत की संविधान पीठ ने अर्दोनी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य बनाने के लिए कोई समय सीमा है तो वे केंद्र से निर्देश प्राप्त कर शीघ्र अदालत को अवगत कारायें।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मुद्दे पर उच्चतम स्तर पर निर्देश प्राप्त करने के बाद अपना रुख स्पष्ट करने के लिए 31 अगस्त तक का समय मांगा। उन्होंने कहा कि वह 31 अगस्त को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति के भाविष्य पर एक विस्तृत बयान देगा। संविधान पीठ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बचाव में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें

सुनने के बाद उनसे केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर को फिर राज्य का दर्जा बहाल करने के संबंध में आधिकारिक बयान देने को कहा।

शीघ्र अदालत ने केंद्र से सवाल किया, क्या



संसद के पास मौजूदा भारतीय राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की शक्ति है। इस पर श्री मेहता ने जवाब दिया कि जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला स्थायी नहीं है। उन्होंने कहा, जब चीजें सामान्य हो जाएंगी तो जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य बना दिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने संविधान पीठ को बताया कि सदन (सांसद) में भी एक बयान दिया गया है और प्रयास किए जा रहे हैं। एक बार प्रयास सफल हो जाएं और स्थिति सामान्य हो जाए तो हम इस (राज्य बनाने) पर विचार करेंगे।

श्री मेहता ने कहा, हम हमेशा राष्ट्रीय एकता के पक्ष में हैं। मैं चुनाव और राजनीति की बात नहीं करूंगा। मैं राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर बात करूंगा। इसमें लोगों की भलाई का ध्यान रखा जा रहा है। इस पर पीठ ने कानून अधिकारी से कहा कि लोकतंत्र की बहाली भी महत्वपूर्ण है। पीठ ने कहा, लोकतंत्र की बहाली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं हो सकती, जहां...कुप्रबंधन (अव्यवस्था) हो। श्री मेहता ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के 5 अगस्त 2019 के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि 2020 में दशकों में पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव हुए और कोई हड़ताल, कोई पथराव, कोई कर्फ्यू नहीं लगाया पड़ा। उन्होंने विकास कार्यों का हवाला देते हुए शीघ्र अदालत को बताया, नाए होटल बनाए जा रहे हैं। फैसले (अनुच्छेद 370 को निरस्त करने) से सभी को फायदा हुआ है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित करना उसी पैटर्न का पालन करता है, जैसा 1966 में सरकार ने पंजाब को विभाजित करके हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश बनाने के लिए अपनाया था, जब वह राष्ट्रपति शासन के अधीन था।

EXPERIENCE THE PURE TASTE OF INDIAN SWEETS

BIKANER SWEETS

Dinesh Chand
Mob.no :-7303458260

Add N.H.-24 .RahulVihar ist
Vijay Nagar (Ghaziabad)

Dry Fruits Sweets | Bengali Sweets
Khoya Sweets | Chikki & Many More

